Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

विश्व का सबसे व्यापक और कारगर
टीकाकरण अभियान

संपादन

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-69047014

विषय सूची

भूमिका

1.	कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत अव्वल	**5**
2.	कोविड-19 अपडेट	**6**
3.	CoWIN एप से टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी	**7**
4.	'वैक्सीन मैत्री' से पूरे विश्व को दिया 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश	**8**
5.	देश में नहीं है कोरोना वैक्सीन की कमी	**9**
6.	कोविड के दौर से कुछ 'सबक' कुछ 'सीख' लेगी दुनिया, भारत दिखायेगा मानव सभ्यता की राह - **शिवानन्द द्विवेदी**	**11**
7.	कोविड-वैक्सीनेशन के मामले में भारत की चमकदार उपलब्धि - **प्रणय कुमार**	**13**
8.	मिलकर जीतना होगा कोरोना से जंग - **सतीश सिंह**	**16**
9.	दुष्प्रचार को नकार आगे बढ़ा टीकाकरण अभियान - **डॉ दिलीप अग्निहोत्री**	**20**
10.	कोरोना से लड़ाई में 'त्रिपुरा अव्वल' - **अभय सिंह**	**24**
11.	बहुत तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान, अंधविरोध से बाज आए विपक्ष - **नवोदित सक्तावत**	**26**
12	प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में आगे बढ़ रहा वैक्सिनेशन अभियान - **महेश तिवारी**	**28**
13.	देश में हर्ड इम्युनिटी क्षमता विकसित करना कोरोना के खिलाफ लड़ाई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लाभकारी सिद्ध होगा - **प्रहलाद सबनानी**	**31**

भूमिका

किसी भी राष्ट्र के चरित्र और उसके नेतृत्व की वास्तविक पहचान संकटकाल में ही होती है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से मुकाबला किया है, वह अन्य देशों के लिए प्रेरणादायी है. हमने अबतक अपने धैर्य, संयम, समझदारी और दूरदर्शिता से इस महामारी का सामना किया है। लगभग 100 वर्षों के बाद ऐसी महामारी का सामना भारत सहित पूरा विश्व कर रहा है। भारत ने जिस तरह पिछले वर्ष ही उचित समय पर लॉकडाउन का निर्णय लिया उसने लाखों भारतीयों की जान बचाई, मगर लॉकडाउन लंबे समय तक नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हराने और सभी को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण ही सबसे कारगर उपाय है। टीकाकरण अभियान पर रणनीति की शुरुआत भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से वर्ष 2020 के अप्रैल महीने में ही कर दी थी, जब कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या महज कुछ हजार थी. उस समय सरकार ने कोरोना वायरस के टीका को विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ. विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित आईएमएफ ने कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की. भारत में अबतक वैश्विक स्तर पर सबसे तीव्र गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और अबतक 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को वैक्सीन लग चुकी है. न सिर्फ देश में बल्कि 'वैक्सीन मैत्री' अभियान के माध्यम से भारत ने अनेक देशों को भारत में निर्मित 'कोवैक्सीन' और 'कोविशील्ड' मुहैया कराकर 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना का मान बढ़ाया है. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने कोरोना महामारी के विरुद्ध भारत के टीकाकरण अभियान पर समाचार पत्रों में प्रकाशित आलेखों में से कुछ चयनित आलेखों को संकलित करके एक बुकलेट का स्वरूप दिया है. इस बुकलेट के माध्यम से पाठक एक ही जगह देश के टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं को पढ़ सकता है. इस संकलन में जितने भी लेख लिए गए हैं, सभी लेखों के लिए अधिष्ठान लेखकों एवं समाचार पत्रों के प्रति आभारी है.

डॉ. अनिर्बान गांगुली

निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत अव्वल

- 16 जनवरी, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया।
- कोविड-19 टीकाकरण की निगरानी, नियंत्रण और समन्वय के लिए केंद्र सरकार ने CoWIN एप का निर्माण किया।
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50.68 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
- भारत इस समय विश्व में सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश है. अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों को पछाड़कर यह उपलब्धि देश ने हासिल की है.
- देश के टीकाकरण अभियान को तब और गति मिली थी जब, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2021 को देश के सभी लोगों को मुफ्त टीके लगाने की नई टीकाकरण नीति को लागू किया। इस नीति का व्यापक असर देखने को मिला और सिर्फ इस दिन 86.16 लाख से अधिक डोज लोगों को दी गईं, जो अब तक की देश में सबसे अधिक संख्या थी। इससे पहले 48 लाख से अधिक डोज एक अप्रैल को लगाई गई थी।
- 22 जनवरी, 2021 को भारत ने सर्वप्रथम सबसे तेज टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया था. जब अमेरिका के 10 दिनों में दस लाख टीके लगाने के मुकाबले भारत ने महज 6 दिन में 10,43,534 लोगों को टीका लगा दिया था.
- गौरतलब है कि भारत में 16 जनवरी, 2021 से टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जबकि अमेरिका में 14 दिसंबर, 2020 को टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया था।
- इसी टीकाकरण अभियान का असर है कि देश में अब कोरोना से रिकवरी की दर बढ़कर 97.28 प्रतिशत हो गई है.

कोविड-19 अपडेट

स्वास्थ्य कर्मी

पहली खुराक
1,03,32,085

दुसरी खुराक
79,74,385

अग्रिम पंक्ति के कर्मी

पहली खुराक
1,82,15,157

दुसरी खुराक
1,17,33,363

18-44 वर्ष आयु वर्ग

पहली खुराक
17,58,22,657

दुसरी खुराक
1,18,44,743

45-59 वर्ष आयु वर्ग

पहली खुराक
11,16,30,145

दुसरी खुराक
4,24,75,061

60 वर्ष से अधिक

पहली खुराक
7,83,78,107

दुसरी खुराक
3,84,04,789

कुल

50,68,10,492

CoWIN एप से टीकाकरण प्रक्रिया की निगरानी

- कोविड-19 टीकाकरण की निगरानी, नियंत्रण और समन्वय के लिए केंद्र सरकार ने CoWIN एप का निर्माण किया।
- CoWIN एप में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था उपलब्ध है।
- टीका लगवाने वाले का पूरा डेटा कोविन एप पर अपलोड होता है। टीकाकरण के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाता है।
- 1075 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कोरोना टीकाकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
- टीकाकरण कार्यक्रम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों को भी टीकाकरण संबंधित सारी जानकारी 12 भाषाओं में एसएमएस द्वारा भी दी जा रही है।

‘वैक्सीन मैत्री’ से पूरे विश्व को दिया ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ का संदेश

- सर्वप्रथम भारत ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना को अन्य देशों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल एवं अन्य दवाओं को भेज कर चरितार्थ किया. जब हमने 150 देशों को दवाओं की आपूर्ति की और इनमें से 80 देशों को दवाएं अनुदान में दी गई।
- मास्क, पीपीई और डायग्नोस्टिक किट का उत्पादन बढ़ने के साथ ही हमने अन्य देशों को भी यह उपलब्ध कराया।
- हमने कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह के टीकाकरण की कल्पना की थी, उसके लिए भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना जरुरी था। जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में डिजिटल माध्यम से दिए गए संबोधन में रख दी गई थी.
- जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि भारत के टीका उत्पादन और आपूर्ति क्षमता का उपयोग इस संकट से निपटने में पूरी मानवता के लिये किया जाएगा।
- हमने टीके की आपूर्ति के लिए शीत श्रृंखला और भंडारण क्षमता को सुदृढ़ बनाने की भी बात की थी। यह दृष्टिकोण केवल वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी सदियों पुरानी परंपरा को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भारत की बढ़ती क्षमताओं का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए करने की मोदी सरकार की सोच को भी ज़ाहिर करता है।
- भारत ने सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने के साथ वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार के साथ, मॉरीशस और सेशेल्स को वैक्सीन दी गई।
- इसके बाद थोड़े दूर पर बसे पड़ोसी देशों और खाड़ी के देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। अफ्रीकी क्षेत्रों से लेकर कैरिकॉम देशों तक वैक्सीन की आपूर्ति करने का उद्देश्य छोटे और अधिक कमजोर देशों की मदद करना था।
- हमारे उत्पादकों ने द्विपक्षीय रूप से या कोवैक्स पहल के माध्यम से अन्य देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने के लिए अनुबंध भी किया है। अभी तक, हमने 95 देशों को लगभग 6.64 करोड़ ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीनों की आपूर्ति की है।

देश में नहीं है कोरोना वैक्सीन की कमी

- कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर अफवाह फैलाने का कार्य किया है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इन अफवाहों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ कोरोना के खिलाफ टीकाकरण पर बल दिया है.
- हाल ही में 14,505 करोड़ रुपये में 66 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया गया है और यह सरकार की तरफ से दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
- ताजा ऑर्डर के तहत सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया दिसंबर तक 50 करोड़ जबकि भारत बायोटेक करीब 38 करोड़ डोज तैयार करेगी। इनमें भारत सरकार को क्रमशः 37.5 करोड़ और 28.5 करोड़ डोज मिलेगी।
- इसके अलावा, वैक्सीन की 22 करोड़ डोज प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी। इस लिहाज से अगस्त-दिसंबर के बीच सरकार के खाते में 96 करोड़ डोज होने का अनुमान है।
- मोदी सरकार ने साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में वैक्सीन के यह ऑर्डर काफी अहम हैं.
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा था कि देश में दिसंबर महीने तक 1.35 अरब डोज वैक्सीन उपलब्ध होगी जो व्यस्क आबादी के लिहाज से पर्याप्त है।
- जिसमें 50 करोड़ डोज कोविशील्ड, 40 करोड़ डोज कोवैक्सिन और 30 करोड़ डोज बायलॉजिकल ई की सबयूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ डोज जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन जबकि 10 करोड़ डोज रूसी वैक्सीन स्पूतनिक वी की शामिल है।
- सरकारी और निजी अस्पतालों के जरिए टीकाकरण हो सके, इसलिए जून महीने में केंद्र सरकार द्वारा 11.46 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए थे। जिसे जुलाई में बढ़ाकर 13.50 करोड़ कर दिया गया।
- वैक्सीन की कमी महज झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं है. क्योंकि जुलाई में राज्यों में वैक्सीन के कितने डोज उपलब्ध कराए जाएंगे, इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यों को 19 जून,

2021 को ही दे दी थी। इसी तरह हर बार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह जानकारी पहले ही दे दी जाती है.

- कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कमी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, परन्तु इन्हीं विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन की जमकर बर्बादी हो रही है.
- हकीकत यह है कि को-विन पोर्टल से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 21 जून, 2021 को 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण के आरंभ वाले दिन जितना टीकाकरण हुआ, उनमें 70 प्रतिशत डोज बीजेपी शासित राज्यों में दी गई। बाकी 30 प्रतिशत डोज में अन्य विपक्ष शासित सभी राज्य सिमट गए।
- केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 37.3 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 30.2 प्रतिशत, राजस्थान में 25 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 5 लाख डोज और पंजाब में 1 लाख डोज बर्बाद हुई है।

कोविड के दौर से कुछ 'सबक' कुछ 'सीख' लेगी दुनिया, भारत दिखायेगा मानव सभ्यता की राह

शिवानन्द द्विवेदी

रहन-सहन और जन-जीवन का संबंध मनोस्थिति एवं शरीर की अनुकूलता पर निर्भर करता है. मनोस्थिति का निर्माण परिस्थितियों से होता है और शारीरिक अनुकूलता हमें अपने वातावरण, पर्यावरण तथा प्रकृति से हासिल हो जाती है.

आज इस सवाल पर व्यापक चर्चा चल रही है कि कोविड-19 के बाद की दुनिया कैसी होगी ? निसंदेह दुनिया में होने वाले बदलावों के बीच भारत भी अछूता नहीं रहेगा. मानव सभ्यता को चुनौती देने वाली महामारी से बाहर निकलने के बाद देश के सामाजिक ताने-बाने, आर्थिक तौर-तरीकों, पर्यावरण के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण, स्वास्थ्य को लेकर परिवारों के नजरिये सहित हमारे विविध कार्यपद्धतियों में बदलाव देखने को मिलेगा. अदृश्य वायरस की वजह से लॉक डाउन के दौर में समाज का हर व्यक्ति भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए 'मन और शरीर' से तैयार हो रहा है. बेशक यह बदलाव फिलहाल आभाषीय न हो किंतु कहना गलत नहीं होगा कि यह मनुष्य के सीखने का दौर है. हम भविष्य के संभावित बदलावों को सीख रहे हैं. चाहें भय वश हो या लक्ष्य वश अथवा बाधा वश ही क्यों न हो, हम नए तौर तरीकों को आजमा रहे हैं.

आज सेवा क्षेत्र के अनेक उपक्रमों से जुड़े लोग 'वर्क फ्रॉम होम' काम कर रहे हैं. बड़े-बड़े मीडिया संस्थान, कंसल्टेंसी फर्म, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र इस कठिन दौर में 'वर्क फ्रॉम होम' के भरोसे ही चल रहे हैं. यह सब तब चल रहा है जब न तो नियोक्ताओं की और न ही काम करने वाले लोगों की मनोस्थिति इसके लिए पहले से तैयार थी. किंतु काम करने की यह नवाचारी संस्कृति इस प्रतिकूल दौर में ही मजबूरी का उपकरण बनकर चल रही है. दरअसल आमूलचूल बदलाव शांतिकाल में नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में ही होते हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में भी आंशिक बदलावों की गुंजाइश तैयार होती दिख रही है. स्कूलों द्वारा ई-लर्निंग तथा ई-क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह आवश्यक भी है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव तात्कालिक नहीं है. तात्कालिक रूप से बेशक इसपर हम नियंत्रण कर लें, लेकिन स्थायी और सुरक्षित समाधान खोजने का रास्ता

वर्षों तक चलने वाला है. ऐसे में यदि 'ई-क्लासेस' की संस्कृति के प्रति हम मन से तैयार होते हैं तो इससे शिक्षा सुलभता भी बढेगी और संसाधनों की बजाय शिक्षा के गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित हो पायेगा.

जिस ढंग से दुनिया के बेहतर स्वास्थ्य ढाँचे इस वायरस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं. दुनिया इसपर जरूर सोच रही है कि भविष्य का स्वास्थ्य मॉडल क्या हो? यह एक ऐसा विषय है जिसपर भारत नेतृत्वकर्ता बनकर दुनिया को 'आदर्श मॉडल' दे सकता है. दरअसल स्वास्थ्य को लेकर दुनिया के जो कथित विकसित मॉडल हैं, वो 'इलाज केंद्रित' हैं. अर्थात उनका स्वास्थ्य चिंतन बीमार होने के बाद की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देता है. भारत अपने पुरातन आरोग्य प्रणाली के साथ एक ऐसे स्वास्थ्य चिंतन पर बात कर सकता है, जिसमें अधिक जोर इसपर हो कि हम 'कम बीमार' लोगों का समाज तैयार करें. सही मायने में 'इलाज के साधन' केन्द्रित संकुचित दायरे से निकलकर संपूर्णता में इसपर बल देना होगा कि किन उपायों से हम कम बीमार लोगों का देश बन सकेंगे. स्वास्थ्य चिंतन का सही दृष्टिकोण यही है. अत: देश को इस चिंतन की तरफ आगे बढ़ना ही होगा.

संवाद और बैठकों को लेकर यह दौर बदलाव के नए द्वार खोलने वाला है. लॉक डाउन के दौरान छोटी-बड़ी कंपनियों ने बैठकों तथा चर्चाओं के लिए डिजिटल एप का सहारा लिया है. बेशक यह वर्तमान में सहूलियत में आजमाई जा रही पगडंडी है. किंतु भविष्य में बैठक, संवाद, चर्चा का मुख्यमार्ग भी यहीं से निकलेगा.

चूंकि अर्थशास्त्रियों द्वारा ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कोविड के बाद सभी औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक कठिनाइयों से गुजरेंगे. ऐसे में रोजगार और वेतन में कटौती से बचने के लिए कंपनियां ऐसे डिजिटल एप को और सुरक्षित एवं आत्मनिर्भरता के साथ विकसित करके श्रम और वेतन में कटौती की बजाय अन्य संसाधनों में कटौती करके नुकसान की भारपाई का रास्ता खोज सकती हैं. निश्चित ही भविष्य में औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्र ऐसे नवाचारों की कार्य-संस्कृति की तरफ जरुर सोचेंगे.

इस दौर से हासिल अनुभव मानव को उसके खान-पान, यातायात, पर्यावरण व प्रकृति के प्रति सजग सोच, शारीरिक दूरी के अभ्यास तथा स्वच्छता के प्रति दृष्टि को प्रभावित करने वाला होगा.

आज हम जिस तरह का जीवन बंद कमरों में जी रहे हैं, वह अतीत में हमारी कल्पना से परे रहा है. किंतु भविष्य की दुनिया में हमें कैसे जीना है उसकी सीख इसी दौर में हमें मिल रही है. आवश्कयता अगर आविष्कार की जननी है तो परिस्थिति हमारे जीवन का अदृश्य शिक्षक भी है. हमें स्वीकारना होगा कि आज का मानव भविष्य की दुनिया के लिए खुद को तैयार करने के प्रशिक्षण काल से गुजर रहा है.

(यह लेख पूर्व में 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित है. लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर रिसर्च फेलो हैं.)

कोविड-वैक्सीनेशन के मामले में भारत की चमकदार उपलब्धि

प्रणय कुमार

प्रकृति अपने ढंग से संतुलन साधती है और निरंकुश, स्वेच्छाचारी, भौतिकवादी सभ्यता को समय-समय पर सचेत करती हुई अविस्मरणीय सीख भी देती रहती है। और निश्चित ही कोविड-19 इसका वर्तमान में सबसे सटीक उदाहारण है. चुनौतियाँ हमारे जीवन में केवल व्यवधान ही नहीं डालतीं, अपितु वह हमारे वैयक्तिक एवं सामूहिक सामर्थ्य, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चारित्र्य और संकल्प-शक्ति की परीक्षा भी लेती हैं। वह हमें उन आंतरिक शक्तियों की अनुभूति भी करा जाती हैं, जो किसी व्यक्ति-समाज-राष्ट्र के भीतर होती तो हैं पर सामान्य परिस्थितियों में हमें उनका भान नहीं रहता। मानव-जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता ही यह है कि वह प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर गतिशील रहता है। अपितु यह कहना चाहिए कि गति ही जीवन है. कोविड-काल में जैसा अभूतपूर्व धैर्य, संयम एवं साहस का परिचय हमने दिया है, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जहाँ कोविड के संक्रामक प्रसार, दुष्प्रभावों को लेकर कनाडा-अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोग सड़कों पर तोड़-फोड़, आंदोलन-उपद्रव करते दिखाई दिए, तमाम पश्चिमी देशों की जनता अपनी ही सरकारों से क्षुब्ध और असंतुष्ट दिखी, वहीं आम भारतीय जनमानस का अपनी सरकार के साथ सहयोग एवं सामंजस्य का रवैया दिखा। वे सरकार की नीति, निर्णय, नीयत और प्रयासों से कमोवेश प्रसन्न या संतुष्ट दिखे। और सरकार ने भी किसी प्रकार की सुस्ती, पंगुता या निष्क्रियता का परिचय न देते हुए कोविड-19 के अप्रसार हेतु निरंतर सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहते हुए सभी आवश्यक क़दम उठाए। संक्रमण के संदिग्धों का व्यापक पैमाने पर परीक्षण करवाया, उसके लिए नई-नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की, संक्रमितों के आइसोलेशन के लिए स्थाई-अस्थाई कोविड-केंद्र खुलवाए, माँग एवं आवश्यकता के अनुपात में वेंटीलेटर्स-बेड्स, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा-किट्स आदि उपलब्ध करवाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, हाथ धोने, सैनेटाइजेशन आदि के लिए जागरुकता-अभियान चलाया, कोविड-काल में यात्रा करने वालों की विधिवत निगरानी रखी, उनसे संबंधित सभी ज़रूरी ब्यौरों को सहेजा-संभाला-साझा किया। इसी कोविड-काल में भारत मास्क और पीपीई किट के आयातक से

निर्यातक बना। कोविड-काल में हमने पुलिस, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मियों, सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्य-निष्ठा एवं सेवा-भाव की ऐसी-ऐसी उजली-मनावीय-ईमानदार तस्वीरें देखीं, जो सहसा विस्मित करती हैं, भविष्य के प्रति उम्मीद जगाती हैं। यों तो पूरी दुनिया के लिए कोरोना जैसी महामारी से लड़ना आसान नहीं था। परंतु भारत जैसे विशाल जनसंख्या एवं भिन्न भौगोलिक संरचना वाले देश के लिए तो यह और भी कठिन था। जहाँ पश्चिम के विकसित देश कोविड से लड़ते-जूझते हुए हाँफते या कदमताल करते दिखे, वहाँ सीमित पूँजी-संसाधनों वाले अंतर्बाह्य चुनौतियों से घिरे देश-भारतवर्ष का कोविड से लड़ना, दृढ़ता एवं सफलता से लड़ना अद्भुत, असाधारण, अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं कि भारत उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित है जिसने कोविड से बचाव के लिए एक नहीं, दो-दो वैक्सीन ईजाद किए। देश के चिकित्सकों-वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि ऐतिहासिक एवं असाधारण है. पर यह समय प्रलय के भविष्यवक्ता बनने का नहीं है। यह समय कोविड-योद्धाओं का मनोबल बनाए रखने का है। यह समय जन-जागरुकता का है। यह समय सावधानी, सतर्कता और सजगता है। यह समय वैक्सीनेशन में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों-चिकित्सकों को हिम्मत-हौसला देने का है। सुदूर अंचलों-गाँवों-पहाड़ियों तक पर जाकर स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीनेशन के अभियान को गति दे रहे हैं। प्रलय के भविष्यवक्ताओं ने कभी यह नहीं बताया कि महज़ एक दिन में 90 लाख से अधिक टीका लगाने का मतलब क्या होता है! मतलब भारत ने एक दिन में (21 जून) - पूरा

इजरायल, हॉंगकॉंग, न्यूजीलैंड, परग्वे, बुल्गारिया, दो नामीबिया, तीन चौथाई स्वीडन, तीन चौथाई जिंबाबवे, चार मॉरीशस, दस मालदीव, पच्चीस समोआ, 50 सेशेल्स, सौ सेंट कीट्स जितनी आबादी को टीका लगा दिया। जी, सही सुना आपने! यह छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। भारत वैक्सीनेशन के इस अभियान में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका जैसे विकसित देशों से बराबरी करना, उसे पीछे छोड़ना बहुत चमकदार उपलब्धि है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका उत्सव मनाने की बजाय कुछ विपक्षी दल आज भी मीन-मेख निकालने में जुटे हैं। वे पॉलियो ड्रॉप से इस अभियान की अन्यायपूर्ण तुलना कर रहे हैं। जबकि वे जानते हैं कि केवल पोलियो ड्रॉप पिलाने में देश को कई-कई दशक लगे थे, जबकि पॉलियो ड्रॉप पिलाने के लिए न तो किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, न जान जाने या संक्रमित होने का जोख़िम था। विपक्षी दलों को सरकार की नीतिगत आलोचना करने, सकारात्मक सुझाव देने का लोकतांत्रिक अधिकार है। पर केवल विरोध के लिए विरोध अनुचित है। सरकार के विरोध के नाम पर वैक्सीनेशन के अभियान को धरातल पर अंजाम देने में जुटे चिकित्सकों-स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को तोड़ना अनुचित है। लगभग रिकॉर्ड 37 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है। कोविड की तीसरी लहर और उसकी आशंकाओं के बीच वैक्सीनेशन की यह रफ़्तार आश्वस्तकारी है। यह

संक्रमण के संदिग्धों का व्यापक पैमाने पर परीक्षण करवाया, उसके लिए नई-नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की, संक्रमितों के आइसोलेशन के लिए स्थाई-अस्थाई कोविड-केंद्र खुलवाए, माँग एवं आवश्यकता के अनुपात में वेंटीलेटर्स-बेड्स, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा-किट्स आदि उपलब्ध करवाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, हाथ धोने, सैनेटाइजेशन आदि के लिए जागरुकता-अभियान चलाया, कोविड-काल में यात्रा करने वालों की विधिवत निगरानी रखी, उनसे संबंधित सभी ज़रूरी ब्यौरों को सहेजा-संभाला-साझा किया।

हमें ऐसी किसी भी लहर की भय और आशंका से लड़ने और उबरने का हौसला देती है। जागरूक एवं देशभक्त नागरिक के रूप में हर नागरिक को न केवल वैक्सीन लगवानी चाहिए बल्कि वैक्सीनेशन के इस अभियान के प्रति पास-पड़ोस-परिचितों को जागरूक भी करना चाहिए। यह न केवल आपद-धर्म, अपितु प्रत्येक देशवासी का नागरिक एवं राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए।

(लेखक शिक्षा-प्रशासक हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

मिलकर जीतना होगा कोरोना से जंग

सतीश सिंह

लगभग 100 वर्षों के बाद फिर से एक बड़ी महामारी का सामना हमारा देश कर रहा है। इसके पहले वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी। इस फ्लू से वर्ष 1918 में दुनियाभर के 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे और करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ भारत में इस फ्लू से 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मौत के ये आंकड़े प्रथम विश्वयुद्ध में मारे गए सैनिकों व नागरिकों की कुल संख्या से ज्यादा थे।

कोरोना महामारी स्पेनिश फ्लू से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बीते 100 सालों में इंसानों ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मामले में अभूतपूर्व प्रगति की है. बावजूद इसके, इस महामारी पर इंसान 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी काबू नहीं पा सका है। हालांकि,वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में कोरोना वायरस के टीका का ईजाद कर लिया है. भारत के वैज्ञानिकों ने भी इस बीमारी की स्वदेशी टीका विकसित करने में सफलता पाई है। आज देश में कोरोना वायरस के स्वदेशी एवं विदेशी टीकाओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जबकि पूर्व में, देश में इतने कम समय में बीमारियों की टीकायेँ विकसित नहीं हो पाती थीं। उदाहरण के तौर पर पोलियो, स्मालपॉक्स, हेपिटाइटिसबी आदि बीमारियों के टीकाओं को विकसित करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए थे.

कोरोना वायरस बहुरुपिया है और बहुत तेजी से अपने रूप को बदल रहा है। फिलहाल, कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वर्जन देश और दुनिया में तबाही मचा रहा है। इसी वजह से कोरोना महामारी के तीसरे लहर के आने की संभावना जताई जा रही है। बहुत ही कम समय में इस वायरस के कई नये रूप देखने को मिले हैं। अपनी इसी ताकत की वजह से देश और दुनिया के डाक्टरों और वैज्ञानिकों को यह वायरस चकमा देने में सफल रहा है.

इस वायरस की टीका बाजार में आ गई है, लेकिन इसे हराने वाली किसी कारगर दवा की खोज अभी तक नहीं की जा सकी है. इसलिए, आज टीका ही संजीवनी है। हालांकि, भारत समेत दुनियाभर में कोरोना के टीका की मांग और आपूर्ति के बीच में अंतर है, क्योंकि टीकाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों की संख्या अभी भी गिनी-चुनी हैं।

देश में कोरोना वायरस की टीका अचानक से विकसित नहीं हुई है। इसे विकसित करने के लिए सरकार शुरू से ही योजनाबद्ध तरीके से काम कर

रही है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2020 के अप्रैल महीने में, जब कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या महज कुछ हजारथी, सरकार ने कोरोना वायरस के टीका को विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। सरकार पिछले साल से ही टीका निर्माताओं को टीका विकसित करने के लिए हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाती रही है। सरकार नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) के लिए भी टीका निर्माताओं की मदद करती रही है। सरकार ने अनुसंधान के लिए भी टीका निर्माताओं को सहायता उपलब्ध करवाई है। टीकाओं के उत्पादन और टीकाकरण की रफ़्तार को बढाने के लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से भी कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। कुछ और टीकाओं का परीक्षण भी देश में अग्रिम चरण पर है। देश में टीकाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी केंद्र सरकार टीका खरीद रही है।

महामारी के तीसरे चरण में बच्चोंपर कोरोना वायरस के द्वारा हमला करने की बात कही जा रही है. इसलिए, बच्चों के लिए 2 टीकाओं को जल्द से जल्द विकसित करने के लिए उसके नैदानिक परीक्षण में तेजी लाई गई है. एक अनुमान के मुताबिक अगस्त या सितंबर महीने तक बच्चों का टीका भारत में उपलब्ध हो सकता है। देश में नेज़ल"टीका को विकसित करने के लिए भी अनुसंधान किया जा रहा है। इस टीका को सिरिंज की जगह नाक में स्प्रे करके दिया जायेगा। अगर यह टीका बाजार में जल्दी आती है तो देश से कोरोना वायरस का सफाया करने में थोड़ी आसानी हो जायेगी।

सरकार ने देश में टीकाकरण की जो रूप-रेखा तैयार की थी, वह बिलकुल सही थी। सरकार ने देश में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण करना तय किया था,

राज्य सरकार टीका खरीद पाने में पूरी तरह से असफल रहे। इस वजह से टीकाकरण की प्रक्रिया के केंद्रीयकरण की मांग फिर से की जाने लगी. राज्य सरकारों द्वारा अठारह साल से चौवालीस साल वालों को मुफ्त में टीकाकरण की मांग भी उठाई गई, लेकिन वे ख़ुद ऐसा कर पाने में विफल रहे।

जिसके तहत पहले बुजुर्गों और स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाना था। यह तय किया गया था कि जिन लोगों को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दिया जाये। देश में टीकाकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल भी रही थी। लक्षित समहू के लोग अपनी बारी आने पर टीका लगवा रहे थे। इस योजना को तैयार करने में राज्य सरकारों के सुझावों को भी शामिल किया गया था। सरकार की यह योजना दूरदर्शिता पूर्ण थी, क्योंकि अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी आमजन के जीवन की रक्षा कर रहे थे। अगर स्वास्थ्य कर्मियों को पहले टीका नहीं दिया गया होता तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती. इसके अलावा, कोरोना वायरस की पहली लहर में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोग ज्यादा संक्रमित हुए थे। इसलिए, उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य था।

कोरोना महामारी के बीच में भी कुछ लोगों के द्वारा यह कहा गया कि केंद्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से महामारी का सामना नहीं कर रही है। अठारह साल से अधिक उम्र वाले लोगों का भी टीकाकरण करना चाहिए। यह भी कहा गया कि राज्य सरकारों को टीकाकरण के मामले में निर्णय लेने, टीका खरीदने, टीका देने के लक्षित समूह को चिह्नित करने आदि की छूट दी जाये, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

इस क्रम में जब केंद्र सरकार ने टीकाओं को खरीदने और लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया तो देशभर में अव्यवस्था फैलने लगी। लक्षित समूह की संख्या में भारी इजाफा होने की वजह से टीकाओं के मांग और आपूर्ति में भारी अंतर आ गया, जिसकी वजह से टीकाकरण में गतिरोध आ गया। हालांकि, अब फिर से टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी आने लगी है। कई राज्यों में लापरवाही की वजह से टीकाओं की बर्बादी भी हुई। लॉकडाउन लगाने के निर्णय लेने में भी राज्य सरकारों द्वारा गलतियाँ की गईं, जिसकी वजह से भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

राज्य सरकार टीका खरीद पाने में पूरी तरह से असफल रहे। इस वजह से टीकाकरण की प्रक्रिया के केंद्रीयकरण की मांग फिर से की जाने लगी. राज्य सरकारों द्वारा अठारह साल से चौवालीस साल वालों को मुफ्त में टीकाकरण की मांग भी उठाई गई,

लेकिन वे ख़ुद ऐसा कर पाने में विफल रहे।

बहरहाल, केंद्र सरकार ने टीकाकरण का केंद्रीयकरण फिर से कर दिया और 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का मुफ्त में टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है, जिससे टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। मामले में अगर कोई निजी अस्तपताल में पैसे देकर टीका लगवाना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। अभी टीकाओं के 75 प्रतिशत की खरीददारी केंद्र सरकार कर रही है और उसके बाद उसका वितरण राज्यों के बीच कर रही है। निजी अस्तपतालों को 25 प्रतिशत टीका खरीदने की छुट दी गई है, लेकिन निजी अस्तपताल टीका की वास्तविक कीमत के ऊपर अधिकतम 150 रुपए ही सेवा शुल्क के रूप में नागरिकों से ले सकते हैं।

भारत के वैज्ञानिकों ने भी इस बीमारी की स्वदेशी टीका विकसित करने में सफलता पाई है। आज देश में कोरोना वायरस के स्वदेशी एवं विदेशी टीकाओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जबकि पूर्व में, देश में इतने कम समय में बीमारियों की टीकायें विकसित नहीं हो पाती थीं। उदाहरण के तौर पर पोलियो, स्मालपॉक्स, हेपिटाइटिसबी आदि बीमारियों के टीकाओं को विकसित करने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए थे.

भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे स्थान पर है. हमारे देश में लगभग 130 करोड़ लोग निवास करते हैं. इतनी बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण तुरत-फुरत में करना आसान नहीं है. हालाँकि, कम जनसंख्या वाले विकसित देश भी अपने सभी नागरिकों का शत-प्रतिशत टीकाकरण नहीं कर सके हैं. इतनी बड़ी महामारी को नियंत्रण करना आसान नहीं है। इस महामारी से लड़ने वाले उपायों को अमलीजामा पहनाने में कठिनाई का आना स्वाभाविक है. इसलिए, आज जरुरत इस बात की है कि देशवासी मिलकर इस लड़ाई में पूरे मन से शामिल हों. यह लड़ाई सिर्फ सरकार की या एक इंसान की नहीं है. इस लड़ाई में किसी भी एक इंसान के कमजोर पड़ने से हम कोरोना से लड़ाई हार सकते हैं. इसलिए, सभी लोग कोरोना से बचाव के सभी मानदंडों का अनुपालन करें. जिन्होंने अपना टीकाकरण करवा लिया वे भी ढिलाई नहीं बरतें. उनके द्वारा भी कोरोना मानदंडों का अनुपालन करना उतना ही जरुरी है, जितना टीका नहीं लेने वालों के लिए.

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। आर्थिक मामलों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

दुष्प्रचार को नकार आगे बढ़ा टीकाकरण अभियान

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

नरेंद्र मोदी विरोधियों के हमलों के अभ्यस्त हो चुके है। विगत बीस वर्षों से वह इन्हें झेलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे, नकारात्मक राजनीति से बेपरवाह वह अपना दायित्व निर्वाह करते है। यही कारण है कि उनकी नेकनीयत पर आमजन के विश्वास कायम है। ताजा प्रसंग कोरोना वैक्सीन का। भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसका निर्माण करके दुनिया को चौका दिया था। दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही थी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने के प्रसंग से इसकी तुलना की थी। सैकड़ों देश भारत से कोरोना वैक्सिन लेने की लाइन में लग गए। लेकिन भारत का विपक्ष इस राष्ट्रीय गौरव से अलग रहा। कोरोना वैक्सिनेशन के संबन्ध में सरकार की नीति दूरदर्शिता पर आधारित थी। इसके चलते किसी प्रकार की भीड़ या अफरातफरी नहीं होती। सवा सौ करोड़ की आबादी में इसका भी ध्यान रखना आवश्यक था। इसके अंतर्गत पहले मेडिकल स्टाफ को प्राथमिकता दी गई। इसी क्रम में अन्य कोरोना वारियर्स को शामिल किया गया। इस व्यवस्था को भी विपक्ष ने मोदी विरोध का बढ़िया अवसर माना। किसी ने पूंछा की मोदी जी कोरोना वैक्सीन कब लगवाएंगे। किसी ने कहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है।

कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कोवैक्सिन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इनका कहना था कि वैक्सीन के प्रति भरोसा पैदा करने के लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी को टीका लगवाना चाहिए। अगर वैक्सीन इतनी ही विश्वसनीय है तो बीजेपी के नेताओं ने सबसे पहले यह क्यों नहीं लगवाई। एक दिग्गज ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है, बिना सोच समझे अनुमति दी गई है जो कि ख़तरनाक हो सकती है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सिन को लेकर संशय जाहिर किया था। डॉक्टरों ने इसको लेकर एक पत्र मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखा था। कोवैक्सिन को जब इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी तब तक इसके तीनों चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने की मांग की थी। जबकि सरकार कहना था कि कोवैक्सिन सुरक्षित है और इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। ऐसे हमले

लगातार चल थे,विपक्ष सोच रहा था कि नरेन्द्र मोदी के पास उनके सवालों का जबाब नहीं है। मोदी भी चुप थे। उनके मन में कुछ और चल रहा था। विपक्षी दिग्गजों को वहां तक अनुमान लगाने का समय भी नहीं है। फिर एक सुबह इलेक्ट्रॉनिक व सोसल मीडिया से पता चला कि नरेन्द्र मोदी ने सुबह साढ़े छह बजे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई थी उसका पालन किया। सोमवार को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भारत बायोटेक की बनाई 'कोवैक्सिन' की पहली खुराक ली थी। राष्ट्रीय हित व गौरव को ध्यान में रखते हुए ट्वीट किया। कहा कि हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोविड के खिलाफ लड़ाई को कम समय में मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। मैं उन सबसे अपील करता हूं कि जो लोग कोरोना टीका लगाने के लिए योग्य हैं वे वैक्सीन लें। मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं।

देश में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने को कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण एक मार्च से शुरू हुआ है। इस चरण में साठ साल से ज्यादा आयु वाले बुजुर्गों के साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त पैतालीस साल या उससे ऊपर की आयु के लोगों को टीका लगेगा। नरेंद्र मोदी को इसी दिन का इंतजार था। वैसे वह सबसे पहले यह वैक्सीन लगावा लेते,तब भी विपक्ष के हमले से नहीं बचते। तब कहा जाता कि नरेन्द्र मोदी को देश की नहीं केवल अपनी चिंता है। वस्तुतः ऐसे हमले ही मोदी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में कोरोना आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पहले ही निःशुल्क वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करायी थी। भारत सरकार इक्कीस देश के अठारह वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक लाभ होगा। क्योंकि प्रदेश में अठारह वर्ष से ऊपर के सोलह करोड़ लोगों को वैक्सीन से आच्छादित करना है। उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट वेण्डर्स के लिए निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रारम्भ किया गया है। स्ट्रीट,वेण्डर्स पटरी दुकानदार,ठेला, खोमचा,रेहड़ी आदि के लिए स्पेशल बूथ बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग किसी भी भ्रम या अफवाह पर ध्यान ना दें। वैक्सीन ही एक मात्र सुरक्षा कवच है। सभी नागरिकों को सुरक्षा कवच देने के लिए वैक्सीनेशन सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने देश को दो स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा कि वैक्सीनेशन कार्य में तीव्रता लाने एवं लोगों को वैक्सीनेशन की सर्वसुलभता हेतु विभिन्न समूहों पर फोकस करते हुए कार्यक्रम बनाये गये हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अभिभावक स्पेशल बूथ पर बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों का वैक्सीनेशन

सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी प्रकार,जूडीशियरी तथा मीडिया के लिए अलग बूथ तथा शिक्षक एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बूथों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वृहद पैमाने पर अठारह वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है। राज्य

सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष दिसम्बर तक अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। इसके पहले चरण में सभी हेल्थ वर्करों को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में एक फरवरी से कोरोना वारियर्स का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन कराया गया। तृतीय चरण में साठ वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन की सुविधा प्रदान की गयी। इसके पश्चात चैथे चरण में पैंतालीस वर्ष से अधिक के आयु के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक मई से अठारह से पैंतालीस वर्ष के आयुवर्ग के लिए निःशुल्क वैक्सीन राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही थी। इक्कीस भारत सरकार इस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह से दस लाख से बारह लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को कोरोना आपदा प्रबंधन पर राष्ट्र को संबोधित किया था। उसी दिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव द्वारा वैक्सीन टीका लगवाया। यह दोनों प्रसंग बिल्कुल अलग है। इनके बीच कोई संबन्ध देखना अजीब लग सकता है। लेकिन नकारात्मक राजनीति के इस दौर में ये दोनों ही प्रकरण सकारात्मक सन्देश देने वाले है। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पिछले कुछ समय से जारी नकारात्मक राजनीति का उल्लेख किया। ऐसा करने वालों ने हर कदम पर भ्रम फैलाया। ऑक्सीजन से लेकर वैक्सिनेशन तक इसके दायरे में थे। लेकिन इन बातों को पीछे छोड़ते हुए नरेन्द्र मोदी ने सभी राज्यों में वैक्सिनेशन व गरीबों को राशन वितरित करने का संकल्प दोहराया। यह उनके सकारात्मक रुख की अभिव्यक्ति थी। मुलायम सिंह यादव ने भी वैक्सीन टीका लगवा कर सकारात्मक सन्देश दिया

है। उन्होंने इसमें कोई राजनीति नहीं देखी। भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण कर दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है। देश के सभी लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। मुलायम सिंह ने बिना कुछ कहे बड़ा सन्देश दिया है। वैक्सीन पर तो पहले दिन से ही जम कर नकारात्मक राजनीति हुई। इसके बाद भी आमजन इससे भ्रमित नहीं हुआ। देश में तेईस करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर रहे थे, तभी हमने तैयारियां कर ली थीं। अप्रैल में जब कोरोना के कुछ हजार केस थे,तभी केंद्र ने वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को हर तरह से सपोर्ट किया गया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लीनिकल ट्रायल में मदद की गई।

रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के जरिए हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले कई समय से देश जो लगातार प्रयास कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने वाली है। नरेंद्र मोदी ने कहा इतने कम समय में वैक्सीन बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि देश में सात कंपनियां अलग-अलग वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जगजाहिर है कि कई मुख्यमंत्री स्वयं ही सभी अधिकारों के लिए बेकरार थे। उन्हें केंद्र का सहयोग पसन्द नहीं था। वह स्वास्थ्य को राज्यों का विषय बता रहे थे। लेकिन ये राज्य उचित व्यवस्था में विफल रहे। पूछा जाने लगा कि सबकुछ भारत सरकार ही क्यों नहीं तय कर रही। राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही। लॉकडाउन की छूट राज्य सरकारों को क्यों नहीं मिल रही है। वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल की दलील दी गई। कहा गया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए इस दिशा में शुरुआत की गई। मोदी ने कहा कि केंद्र ने एक गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकें।

वैक्सीन आई तो शंकाओं-आशंकाओं को बढ़ाया गया। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ,तभी से कुछ लोगों ने ऐसी बातें कहीं जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हुई। कोशिश ये भी हुई कि वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त हो,बाधाएं आईं। भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका और आशंका को बढ़ाया गया। भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका और अफवाहें फैला रहे हैं,वो भोले-भाले भाई-बहनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। देश वैक्सीनेशन को तेज गति से संचालित किया जाएगा।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

कोरोना से लड़ाई में 'त्रिपुरा अव्वल'

अभय सिंह

केंद्र बीते डेढ़ साल में देश ने आपसी सहयोग और एकजुट प्रयासों से कोरोना महामारी से मुकाबला किया है और आगे भी इसी सहयोग के बलबूते हम अपने प्रयत्नों से इस लड़ाई में विजयी होंगे। बहरहाल, जहां हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर कोविड केस बढ़ने वाले राज्यों में केरल का नाम अवश्य रहा है। मगर, वामपंथियों से विशेष हमदर्दी रखने वाले एक विशेष वर्ग ने बड़ी चालाकी से इस तथ्य को छिपाया है और कोरोना मामलों में गिरावट आते ही अचानक 'केरल मॉडल' को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर राज्य की उपाधि दे दी जाती है। जबकि यहां चर्चा की जानी चाहिए 'त्रिपुरा मॉडल' की, जिसने विभिन्न बाधाओं को पीछे छोड़कर टीकाकरण अभियान में अन्य राज्यों के सामने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है। त्रिपुरा ने भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद कोरोना से निपटने में जिन नवाचारों का उपयोग किया, जो योजनाएं बनाईं, जिस प्रकार टीकाकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और टेस्टिंग पर विशेष बल दिया। यह एक आदर्श मॉडल है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा त्रिपुरा राज्य को 31,80,960 वैक्सीन डोज की आपूर्ति की गई है और अबतक 30,35,546 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे 'सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन' अभियान की महत्ता को समझते हुए और तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री बिप्लब कुमार देब ने राज्य में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया। इसी सजगता के कारण त्रिपुरा में 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का 98 प्रतिशत और 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का 80 प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। इनमें सभी नागरिकों को एक डोज कम से कम लग चुकी है। त्रिपुरा के 8 जिलों की जनसंख्या लगभग 37 लाख है और उसमें भी भौगोलिक चुनौतियों से जूझते हुए वैक्सीनेशन करना कठिन कार्य है। लेकिन, त्रिपुरा ने यह कार्य सकारात्मक सोच के साथ किया है। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रचार को लेकर व्यापक अभियान चलाया गया। जिसका नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने किया। जनता को टीकाकरण के संबंध में जागरूक करने हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में पब्लिक ऑडियो सिस्टम और पैम्फलेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में 50 हजार कर्मचारियों,

20 हजार स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस आदि की सहायता से हजारों वैक्सीनेशन कैम्प लगाए गए। आशाकर्मियों की मदद से डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन अभियान आदिवासी क्षेत्रों में चलाया गया। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कुछ दिन पहले ही यह बताया था कि, 'त्रिपुरा के विभिन्न जिलों के 73 ग्राम पंचायतों में 100 प्रतिशत टीकाकरण किया जा चुका है।' हाल ही में त्रिपुरा के एक आदिवासी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा था, वहां के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 105 वर्षीय महिला तारकन्या देबबर्मा टीकाकरण के लिए आईं थीं। उनसे मुलाकात के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करते हुए कहा था, 'अगर वह टीका ले सकती हैं, तो आप सभी को किसने रोका है? तुरंत वैक्सीन लें।' वर्तमान में पूरा देश वैक्सीनेशन की ओर तेजी से अग्रसर है और इस लिहाज से त्रिपुरा अन्य राज्यों के लिए आदर्श हो सकता है। त्रिपुरा ने अबतक 90.5 प्रतिशत 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले योग्य व्यक्तियों का टीकाकरण किया है और जल्द ही 100 प्रतिशत टीकाकरण कर लेगा। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक लगातार केस बढ़ने से कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में 23 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज भी जारी किया था। कोविड से लड़ाई में टेस्ट, ट्रैक, और ट्रीट के बाद अब वैक्सीन सबसे कारगर कदम है और त्रिपुरा की भांति अन्य राज्य भी इसे अपनाकर इस महामारी को परास्त करने की ओर सफलतापूर्वक बढ़ सकते हैं।

(लेखक डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

बहुत तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान, अंधविरोध से बाज आए विपक्ष

नवोदित सक्तावत

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के धीमा पड़ते ही देश फिर से संभलने लगा है। सरकार के प्रतिबंधात्मक उपायों ने अपना काम किया और संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफलता मिली। दूसरी तरफ समानांतर रूप से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान ने उम्मीद की किरण जगा दी है। केवल दो महीने पहले अप्रैल में कोरोना की विभीषिका झेल रहे देश में मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया है। टीकाकरण अभियान अब महाअभियान का रूप ले चुका है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कागजों पर नहीं वरन ठोस धरातल पर साफ दिखाई दे रहा है। देश के तमाम छोटे-बड़े शहरों, गांवों व कस्बों में वैक्सीन लगवाने के लिए अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है और यही एक राष्ट्र की जीत है। सामूहिक प्रतिभागिता ही इस अभियान को वृहत्तर बना रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले दिनों भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण करके नया कीर्तिमान बनाया वहीं इसके बाद अलग-अलग दिनों में शहरों ने भी अपने स्तर पर रिकॉर्ड टीकाकरण के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, कई ग्राम पंचायतों में सौ फीसदी टीकाकरण हो चुका है।

कई शहरों में ऑटो-रिक्शा चालक अब उनके वाहनों पर वैक्सीन का प्रमाण-पत्र चस्पा कर रहे हैं और निश्चिंत होकर अपना कार्य कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि आगामी जुलाई माह में बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल शुरू होने जा रही है। जल्द ही इसके आशानुरूप परिणाम सामने होंगे। यद्यपि गैर भाजपा शासित राज्यों या यूं कहें कांग्रेस शासित राज्यों ने इस आपदा में भी अपनी ओछी राजनीति को चमकाने का अवसर खोज लिया। राजस्थान में बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी की गई। ये खबरें जब मीडिया के माध्यम से सामने आईं तो इस पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। एक तरफ जीवनरक्षक वैक्सीन और दूसरी तरफ नफरत एवं हीनता में झुलसता राजनीतिक बोध।

दूसरी तरफ पंजाब में वैक्सीन का ही सौदा कर डाला गया। हालांकि विवाद बढ़ने पर निर्णय वापस ले लिया गया, मगर पंजाब सरकार की असलियत तो सामने आ ही गई। केंद्र सरकार से जिस दाम में वैक्सीन मिलती थी, वहां राज्य सरकार के

दोषी अधिकारियों ने उसी वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया। यानी ये लोग इसमें भी कमाई का अवसर खोज रहे थे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार जनता से कह चुके थे कि कोरोना की दोनों स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड बेहद कारगर है और इन्हें लेने में कोई समस्या नहीं है। एम्स के शीर्ष अधिकारी भी पुष्टि कर चुके थे कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और वैक्सीन लगवाएं। लेकिन कांग्रेस सरकारों की लापरवाही और बदनीयती के कारण केंद्र सरकार का यह महती मिशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिरकार स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल की। उन्होनें बीड़ा उठाते हुए अहम घोषणा की और वैक्सीन अभियान का समस्त दायित्व केंद्र सरकार के हाथों में ले लिया। इसके साथ ही देश की समस्त जनता के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध हो जाने का रास्ता खुल गया। सरकार की इस बड़ी घोषणा को मास्टरस्ट्रोक भी कहा जा सकता है। जब से केंद्र सरकार ने टीकाकरण का प्रबंधन पूरी तरह से अपने हाथ में लिया, विपक्षियों एवं कांग्रेसियों की मानो बन आई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब से ये केवल सरकार को कोसने का कोई बहाना ही ढूंढ रहे। अब चूंकि पिछले दिनों देश में टीकाकरण ने महाअभियान का रूप लिया और एक दिन में रिकॉर्ड 86 लाख से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो गया तो विपक्ष के बड़बोले नेता, पत्रकार आदि का गिरोह एकाएक सक्रिय हो गया। वे इस अभियान की पल्स पोलियो अभियान से बेतुकी तुलना करने लगे और आंकड़ों की दुहाई देते हुए इसे असफल साबित करने के कुत्सित प्रयास में जुट गए। पल्स पोलियो अभियान और कोरोना टीकाकरण दो अलग-अलग विषय हैं। न तो ये बीमारियाँ एक सी हैं और न इनके टीके। ऐसे में दोनों की तुलना करना निरर्थक है। लेकिन सरकार की सफलता से बौखलाए विपक्षी अब इस अभियान में ही मीन मेख निकालकर अपनी संकीर्ण राजनीति का प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। यह बात अलग है कि इन लोगों के अनर्गल प्रलाप से सरकार और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा, टीकाकरण अभियान में तेजी ही आई है। अस्पतालों, वैक्सीनेशन सेंटर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों , जनपद पंचायत भवन और शासकीय कार्यालयों में किए जा रहे टीकाकरण में बड़ी संख्या में नागरिक उमड़ रहे हैं और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। भारत के टीकाकरण अभियान की रफ़्तार विश्व में सर्वाधिक है। निश्चित ही टीकाकरण की इस गति से कोरोना महामारी को खत्म करने की दिशा में देश तेजी से बढ़ेगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

प्रधानमंत्री के कुशल निर्देशन में आगे बढ़ रहा वैक्सिनेशन अभियान

महेश तिवारी

विश्व का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभियान इस समय भारत में चल रहा है। कोरोना महामारी से बचाव का कोई एकमात्र उपाय है तो वह वैक्सिनेशन ही है। ऐसे में देश में काफ़ी तेज़ी के साथ चरणबद्ध तरीक़े से वैक्सिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मोदी सरकार की सफ़लता ही कही जाएगी कि इतने बड़े देश में भी वैक्सिनेशन अभियान काफ़ी प्रभावी और व्यवस्थित रूप से चल रहा है। वैक्सिनेशन अभियान की सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर सतत निगरानी भी कर रहें है। गौरतलब हो कि एक समय ऐसा था जब विपक्षी जमात लगातार वैक्सिनेशन को लेकर दुष्प्रचार कर रहें थे। भारत के लोगों में संशय की स्थिति पैदा कर रहें थे और अब वही विपक्षी नेता वैक्सीन विदेशों को क्यों भेजी गई? इसको लेकर सत्ता पक्ष को घेर रहें। एक बात तो है। आज के समय में विपक्ष बिन पेंदी का लोटा बनकर रह गया है। जिसे हर तरफ़ से सिर्फ़ सत्ता पक्ष की बुराई करनी है। फ़िर वह चाहें किसी भी तरीक़े से। वही देश में लगातार चल रहा है। कभी विपक्षी कोरोना वैक्सीन को 'मोदी वैक्सीन' बता रहें थे। उसके बाद वैक्सीन विदेश क्यों गई। इस बात पर भी बेज़ा विवाद खड़ा किया, लेकिन बाद में एक स्थिति ऐसी भी आई। जब विपक्ष के कई नेताओं को मोदी के वैक्सिनेशन कार्यक्रम की प्रशंसा करनी पड़ी। फ़िर भी वे मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं कर पाएं।

बता दें कि जब 21 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मोदी सरकार ने वैक्सिनेशन के लिए नई नीति का ऐलान किया तो उस समय मोदी सरकार की तारीफ़ कई विपक्षी नेताओं ने भी की। पीएम मोदी ने चूंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही। फ़िर मोदी के इस कदम की पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन समेत कई मुख्यमंत्रियों ने तारीफ की।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा को देरी से लिया गया निर्णय बताते हुए कहा कि, " टीके की निरंतर आपूर्ति केन्द्र सरकार कैसे करेगी, यह सबसे बड़ी चुनौती है।" मतलब एक तरफ़ प्रशंसा भी की गई तो दूसरी तरफ़ सवाल उठाने से भी बाज नहीं आए। यही हाल बाक़ी के कई मुख्यमंत्रियों का भी रहा। वहीं मालूम हो कि एक समय ऐसा था कि

वैक्सिनेशन को लेकर देश के लोगों में चौतरफ़ा भय का माहौल व्याप्त था। एक तरफ़ विपक्ष वैक्सीन को लेकर आम जनता को भर्मित कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ़ वैक्सीन के फ़ायदे और नुक़सान को लेकर भी समाज में डर का माहौल था। इतना ही नहीं कई क्षेत्रों में रूढ़िवादिता और अन्य तरीक़े की बातें भी वैक्सिनेशन की राह में रोड़े अटका रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ख़ुद इन सबसे निपटने के लिए कमर कसी। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने समय-समय पर जनता को वैक्सिनेशन के लिए अपने भाषणों के माध्यम से प्रेरित करते रहें।

इतना ही नहीं इसी बीच प्रधानमंत्री लगातार वैक्सिनेशन के बारे में चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक भी करते रहें। जिसका नतीजा यह हुआ कि तमाम दिक़्क़तों के बावजूद भारत ग्लोबल वैक्सिनेशन ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी व फ्रांस जैसे देशों के समतुल्य आकर खड़ा हो गया। एक समय था जब भारत मे वैक्सिनेशन की रफ्तार काफी धीमी थी, उस विकराल परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने वैक्सिनेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। उसका असर यह हुआ कि भारत में वैक्सिनेशन की रफ़्तार विश्व भर में सबसे तेज हो गई। भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में जून महीने के अंत तक कुल वैक्सिनेशन 32.36 करोड़ डोज हो चुकी थी। वही अमेरिका में 32.33 करोड़ वैक्सिनेशन की डोज दी गई थी। गौर करने वाली

बात तो यह है कि तमाम देशों की तुलना में भारत में टीकाकरण अभियान देरी से शुरू हुआ था। बावजूद इसके आज हम वैक्सिनेशन के मामले में शीर्ष देशों में शामिल हो गए है।

हम अब वैक्सिनेशन के मामले में सिर्फ़ शीर्ष पर ही नहीं हैं। बल्कि अफ्रीका के गुमनाम देशों से लेकर कैरेबियन देश सेंट लूसिया तक भारत की वैक्सिनेशन पहुँच रही है।

कोरोना महामारी के दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। उस स्थिति में भी देशवासियों को फ्री वैक्सीन देने का फ़ैसला लेकर कहीं न कहीं मोदी सरकार ने यह साबित किया कि उनके लिए पहले देशवाशियों की जान है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों को फ्री वैक्सीन देने का फैसला किया। हालांकि भले विपक्ष इसे देरी से लिया गया फ़ैसला बताती हो, लेकिन जिस तरीक़े का कुशल प्रबन्धन मोदी सरकार ने कोरोना से बचाव और वैक्सिनेशन को लेकर किया। वह काबिलेतारीफ है। इतना ही नहीं अगर किसी और दल की सरकार केंद्र में इस दौरान होती तो एक बात तय थी कि देश की स्थिति काफ़ी पतली हो सकती थी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की कमी हमेशा देखी गई। फ़िर वह चाहें कोई भी आम जनमानस से जुड़ा सवाल रहा हो।

बता दें कि सभी को मुफ़्त वैक्सीन के इस निर्णय के तहत 21 जून से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के देश के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन दी जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सिनेशन पॉलिसी पर राजनीति करने वालों को भी समय-समय पर डोज देने का काम किया है। इतना ही नहीं यह मोदी सरकार के नेतृत्व का ही कमाल है कि 21 जून को देश में एक दिन में ही क़रीब वैक्सिनेशन के 80 लाख डोज़ देकर कीर्तिमान स्थापित किया गया। ऐसे में कुछ भी हो और विपक्ष बेवज़ह की चाहें कितना भी राजनीति करें, लेकिन मोदी सरकार को पता है कि जान है तो जहान है। जिसको बचाने के लिए वह युद्ध स्तर पर वैक्सिनेशन प्रोग्राम को चला रही ताकि कोरोना की आगामी लहरों से बचा जा सकें और देश से कोरोना नामक महामारी दूर हो सकें। बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) का महाअभियान सफ़ल हो। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वैक्सिनेशन के काम में लगिए। लाइन में खड़े होकर देखिए लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? साथ ही इस पर सरकार स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम करने का भी सोच रही। जिसके लिए बीते दिनों प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा भी की। कुल-मिलाकर अगर ऐसे ही मोदी सरकार का वैक्सिनेशन अभियान चलता रहा तो जल्द ही देश कोरोना महामारी से छुटकारा पा सकता है और जिसके लिए अगर कोई बधाई का पात्र होगा तो वह प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उनके कार्य करने का तरीका है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

देश में हर्ड इम्युनिटी क्षमता विकसित करना कोरोना के खिलाफ लड़ाई और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लाभकारी सिद्ध होगा

प्रहलाद सबनानी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा देश में कोरोना महामारी के बचाव के लिए 24 घंटे सातों दिन टीका लगाये जाने की व्यवस्था कुछ ही समय में विकसित किए जाने की अनुशंसा की है ताकि टीका लगाए हुए लोगों के दायरे को बढ़ाते हुए देश की अर्थव्यवथा को पुनः तेजी से दौड़ाया जा सके। हाल ही में जारी किए गए अपने मासिक प्रतिवेदन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि देश में झुंड प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए 70 करोड़ युवाओं को टीके की कम से कम खुराक 30 सितम्बर 2021 के पूर्व लगाई जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे देश के उपभोक्ता एवं उत्पादकों में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा एवं यह आर्थिक विकास को शीघ्र ही गति देने में सहायक सिद्ध होगा। इसका आशय यह है कि अगले केवल लगभग 3.5 माह के दौरान लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिदिन टीका देना होगा तभी उक्त लक्ष्य को 30 सितम्बर 2021 तक हासिल किया जा सकता है।

देश में आज की परिस्थितियों में देशवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए उन्हें टीका लगाना ही एकमात्र उपाय उपलब्ध है। कोरोना महामारी की प्रथम लहर के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो रही थी कि अचानक दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को पुनः एक झटका दे दिया। स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था दोनों ही नजरियों से टीका ही एक उपाय के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। टीका लगाने से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है अथवा यदि कोरोना से संक्रमण होता भी है तो यह उतना पैना नहीं होगा कि संक्रमित व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए। देश की कुल जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग का टीकाकरण कर लिया जाय अब इस ओर केंद्र सरकार द्वारा

गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। इससे देश में कोरोना से लड़ाई के विरुद्ध आत्मविश्वास पैदा होगा। लोग बगैर किसी डर के घरों से बाहर निकल सकेंगे और इससे बाजारों में रौनक पुनः लौट सकती है। देश की बड़ी आबादी पर्यटन के लिए अपने शहरों से बाहर जा सकती हैं। निर्माण उद्योग भी पुनः अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है इससे पर्यटन एवं निर्माण के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार का सोचना है कि 30 सितम्बर 2021 के पूर्व देश में 70 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लिया जाय। केंद्र सरकार ने, टीका उत्पादकों से चर्चा करने के उपरांत, ताकि आगे आने वाले समय में टीकों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी खड़ी न हो, अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जा रहा है। अब टीकों की उत्पादकों से अभिप्राप्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी इससे राज्य सरकारों पर दबाव कम होगा और राज्य सरकारें केवल टीकाकरण की ओर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। टीकाकरण का पूरा खर्च भी अब केंद्र सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा।

टीकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए टीकों के निर्माण को बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। साथ ही अन्य देशों में टीकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों को भी भारत में ही इन टीकों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब टीकों का निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा निर्मित किए गए 100 टीकों में से 75 प्रतिशत टीके केंद्र सरकार द्वारा खरीदे जाएंगे एवं शेष 25 प्रतिशत टीके इन कम्पनियों द्वारा बाजार में बेचा जा सकेगा। इससे इन कम्पनियों को यह निश्चिंतिता रहेगी कि उनके द्वारा उत्पादित टीकों का 75 प्रतिशत भाग तो तुरंत ही बिक जाएगा।

ग्रामीण इलाकों को भी टीकाकरण के दायरे में लाकर ग्रामीणों का टीकाकरण तेजी से हो इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने ग्रामीणों को भी प्रभावित किया है। इस तरह से कुल मिलकर सभी मोर्चों पर कार्य किया जा रहा है। देश में सभी समाजों एवं निजी क्षेत्र को भी इस काम में मदद करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। अकेले केंद्र सरकार यह इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकती है। टीकों के निर्माण, अभिप्राप्ति के साथ साथ टीकों के वितरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी राज्य में टीकों की उपलब्धता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े। दूर दराज़ ग्रामीण इलाकों में भी टीका समय पर उपलब्ध रहे इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लक्ष्य बहुत ही बड़ा है परंतु देश में इस समय इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अभी लगभग 30 लाख टीके प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं

इसे बढ़ाकर एक करोड़ से अधिक टीके प्रतिदिन तक ले जाना है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह कार्य तो करना ही होगा।

सबसे पहिले स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य सेवाओं में कार्यरत लोगों को टीका लगाया गया इसके बाद 60 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को और अब 18 वर्ष से अधिक की आयु का लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोरोना महामारी के समय में अस्पतालों में टीका लगाने वाले लोगों की भीड़ नहीं हो। हालांकि कोरोना के संक्रमण के धीरे धीरे कम होने के साथ ही अब कुछ जगह पर वॉक इन टीका लगने का काम भी शुरू किया जा चुका है। अब तो धीरे धीरे और भी छूट दी जा सकती है जैसे पंजीकरण कराने के बाद अब कहीं भी और कभी भी टीका लगवाया जा सकता है। अब टीका लगाने की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया जा रहा है। शुरुआत में जरूर कुछ नियम बनाए गए थे ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।

भारत में आज डिजिटल, संप्रेषण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत हो गई है अतः देश में इस प्रणाली का भी पूरा पूरा लाभ लिया जा सकता है। भारत में अपार क्षमताएं एवं सम्भावनाएं मौजूद हैं जिनका पूरा उपयोग करते हुए प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। टीकाकरण के कार्यक्रम में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल भी किया जा रहा है पंजीकरण कराने के साथ ही टीका लगे हुए व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस प्लैट्फोर्म का उपयोग किया जा रहा है।

अब तो कोरोना महामारी का दूसरा दौर ढलान पर है एवं देश में टीकाकरण के कार्य में भी तेजी लायी जा रही है ऐसे में अब केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत ख़र्चों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि रोजगार के नए अवसर निर्मित हों और उत्पादित वस्तुओं की मांग पैदा हो। इससे देश के गरीब वर्ग में आत्मविश्वास पैदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। केवल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें ही क्यों अब तो निजी क्षेत्र को भी आगे आना चाहिए और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता सूची में डालकर शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किए जाने चाहिए। निर्माण क्षेत्र को गति दी जानी चाहिए एवं ग्रामीण इलाकों में नए नए अस्पतालों का निर्माण भी किया जा सकता है ताकि ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सके। इन सभी उपायों से देश की अर्थव्यवस्था में पुनः एक बार V आकर की रिकवरी प्राप्त की जा सकती है।

(लेखक बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं। आर्थिक विषयों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

AIIMS
DELHI
STOP!